इतिहास के दोराहे पर भारत– बांग्लादेश

डॉ. संजय कुमार
सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र, योगदा सत्संग कॉलेज राँची।

आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को हुआ जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के सैन्य कमांडर जनरलए. ए. के. नियाजी ने भारत की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख अपने 93000 सैन्य कर्मियों और अन्य पाकिस्तान अधिकारियों के साथ आत्म समर्पण किया लेकिन वास्तव में देखें तो बांग्लादेश की कहानी मोटे तौर पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही शुरू हो जाती है। तब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा शासन किया जा रहा था। भारत में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े लुटेरे को गवर्नर जनरल एवं वायसराय की संज्ञा दी जाती थी और इस पद पर कर्जन था जो पूरी तरीके से साम्राज्यवादी भावना से ओतप्रोत था, अंग्रेजों की जातीय सर्वोच्चता में विश्वास करता था और बांटो और राज करो की नीति का हिमायती था। उसने भारत के तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी के लोगों की राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के उद्देश्य से बांटो और राज करो की नीति का सफल प्रयोग किया। उसने मुस्लिम नेताओं को विश्वास दिलाया की बंगाल में हिंदू जनसंख्या अधिक है और अगर कभी स्वशासन मिलता है तो उन्हें उन हिंदुओं के अधीन रहना पड़ेगा जिस पर वे सदियों से शासन करते आए हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं को अपने विश्वास में लेकर कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। मुस्लिम बहुल जिलों को मिलाकर पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल इलाकों को लेकर पश्चिम बंगाल का निर्माण किया गया लेकिन तब के बंगाल के लोगों की भावनाएं कुछ अलग थी। हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने मिलकर बंग भंग का विरोध करना शुरू किया और इसे शेष भारत से भरपूर समर्थन मिला। स्थिति को हाथ से निकलता देखकर ब्रिटिश सरकार ने बंग भंग वापस ले लिया और तत्कालीन रूप से बंगाली राष्ट्रवाद ने सांप्रदायिक.विभाजनकारी और साम्राज्यवादी तत्वों को करारी शिकस्त दी। आगे चलकर अंग्रेजों ने फिर से बंगाल को 1912 में बांटा लेकिन इस बार विशुद्ध प्रशासनिक आधार पर बिहार और उड़ीसा प्रांत का निर्माण किया गया। एक बार को लगा था कि अंग्रेज अपने उद्देश्य में सफल हो चुके हैं लेकिन आने वाले समय ने साबित किया की 1905 की बंगाल विभाजन की घटना ने एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव रख दी है जो आगे चलकर न सिर्फ बंगाल में भयंकर सांप्रदायिक तनाव, उन्माद दंगा और जनसंहार का कारण बनी बल्कि भारत के विभाजन की नींव भी साबित हुई और अपने राष्ट्रवाद और बौद्धिक व्यवहार के लिए जाने जाने वाले बंगाल के भी दो टुकड़े हो गए जब यह प्रांत दो भागों में बट कर पश्चिमी भाग भारत में रह गया और पूर्वी मुस्लिम बहुल भाग पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा कहलाया।

अगर हम इतिहास के पन्नों को टटोलें तो पाएंगे की पूर्वी बंगाल का पाकिस्तान का हिस्सा बनना महज संयोग था। यह बात ठीक है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना में ढाका के नवाब का प्रमुख योगदान था और मुस्लिम लीग की जड़े परतंत्र भारत के बंगाल प्रांत में बहुत गहरी थी और मुस्लिम लीग ने यहां अपनी सरकार भी कायम कर ली थी, सच तो यह है कि पाकिस्तान का विचार बंगाल के भद्र मुस्लिम परिवारों से ही खाद पानी पाता था लेकिन यह भी सच है की बंगाल के मुस्लिम नेताओं ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुस्लिम लीग के अखिल भारतीय ढांचे का उपयोग किया। बंगाल प्रांत की मुस्लिम लीग की सरकार के प्रधानमंत्री फजलुल हक और हुसैन मोहम्मद सोहरावर्दी आखरी दम तक प्रयास करते रहे कि पूरे बंगाल को अंग्रेज भारत से अलग स्वतंत्र बंगाल राष्ट्र के रूप में मान्यता दें जो की एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र होता लेकिन भारत के राष्ट्रवादी नेताओं जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता और संकल्प के कारण बंगाल के पूर्वी भाग को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा लिया गया। कुटिल अंग्रेजों ने भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुहरावर्दी की मांग के साथ अपनी सहमति नहीं दिखाई।

पूर्वी पाकिस्तान लंबे समय तक अपने पश्चिमी हिस्से के साथ नहीं रह पाया। सबसे पहले भाषा को लेकर उनका देश के पश्चिमी हिस्से के लोगों के साथ टकराव हुआ जिन्होंने उर्दू को एकतरफा पाकिस्तान की राजभाषा घोषित कर दिया था और इसे पूर्वी भाग के बंगालियों पर भी थोप दिया था जो कि पाकिस्तान की जनसंख्या के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते थे। मोहम्मद अली जिंदा के द्वारा ढाका विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण में स्पष्ट रूप

से कहा गया की बंगाल के लोग स्थानीय स्तर पर बंगाली भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी। मोहम्मद अली जिन्ना के इस भाषण को पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली भद्रलोक ने कभी भी स्वीकार नहीं किया और यह पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से मनमुटाव का प्रमुख कारण बन गया। आगे चलकर बंगालियों ने महसूस किया कि पश्चिमी पाकिस्तान उनका आर्थिक शोषण कर रहा है। तब पाकिस्तान की आय का मुख्य साधन जूट, कपड़ा और चाय उद्योग था जिसका केंद्र पूर्वी पाकिस्तान था लेकिन इन वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त आय का इस्तेमाल मुख्य रूप से पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के लिए किया जाता था। पाकिस्तान की सेवा में मुख्य रूप से पश्चिमी पाकिस्तान और उसमें भी पंजाब के हिस्से के लोग हावी थे और बंगालियों को आमतौर पर फौज के लिए नजरअंदाज किया जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बंगालियों को नाटा, ठिगना,कुरूप और युद्ध लड़ने के लिए नाकाबिल मानते थे। न्यायपालिका, नागरिक प्रशासन तथा अर्धसैनिक बलों में भी पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूरी तरीके से हावी थे और बंगाल के लोगों को नाम मात्र का प्रतिनिधित्व दिया जाता था। यह ठीक है कि कुछ बंगालियों जैसे इस्कंदर मिर्जा और हुसैन शहीद सुहरावर्दी को पाकिस्तान का नेतृत्व करने के लिए अवसर मिला लेकिन कभी भी वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और न हीं पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं, अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व ने उन्हें कुछ करने का अवसर दिया। 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने यह देखा कि उनके सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान की सुरक्षा को ही पाकिस्तान की सुरक्षा के रूप में देखता है और अगर भारत पूर्वी हिस्से पर आक्रमण का इरादा कर ले तो उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। इस दौर में पाकिस्तान में अयूब खान और याहया खान का सैन्य शासन चल रहा था जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने को पूरी तरीके से उपेक्षित पाया। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव करवाए गए जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में प्रभाव रखने वाली अवामी लीग को पाकिस्तानी संसद में बहुमत प्राप्त हुआ लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में प्रभाव रखने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के प्रभाव में सैन्य शासको ने अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया, उन्हें और उनके तमाम प्रमुख राजनीतिक सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने के आरोप में पश्चिम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कोटलखपत जेल में कैद कर लिया गया जिसने पहले से ही राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक रूप से नजरअंदाज किए जा रहे और शोषण का शिकार हो रहे बंगालियों को सुलगा दिया। उनके प्रतिरोध का जवाब पाकिस्तानी सैन्य तंत्र ने बुद्धिजीवियों के कत्लेआम और बंगाली महिलाओं के सामूहिक बलात्कार से दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट में एक अनुमान के अनुसार 3 लाख से अधिक बंगाली बुद्धिजीवियों को मार दिया गया और लगभग 30 लाख बंगाली महिलाओं का बलात्कार किया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासको ने बंगाल में ऐसे कैंप स्थापित किए थे जहां युवा बंगाली महिलाओं को सैन्य कर्मियों की यौन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सामूहिक रूप से मजबूर किया जाता था और जिसका एक उद्देश्य उन्हें पंजाबी मूल के सैन्य कर्मियों के द्वारा गर्भवती बनाकर बंगालियों का नस्ल परिवर्तन करना था। पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या में लगभग 23% हिस्सा हिंदू धर्म मानने वालों का था जिनके ऊपर विशेष रूप से जुल्म किए गए। न सिर्फ उनकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया बल्कि बच्चों, पुरुषों को मारा काटा गया, उन्हें गोमांस खाने पर मजबूर किया गया और उनका सामूहिक जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया गया। पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर करोड़ों की संख्या में बंगालियों ने भारत के पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और बिहार प्रांत में शरण ली। भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों का ध्यान पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा अपने ही देश के पूर्वी भाग के नागरिकों के शोषण अत्याचार, बलात्कार और कत्लेआम की ओर खींचने का प्रयास किया और जोर देकर कहा कि भारत वहां से आ रहे करोड़ों शरणार्थियों का बोझ लंबे समय तक नहीं उठा पाएगा लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान को एशिया में अपना सैन्य साझेदार मानते थे तथा सोवियत संघ एवं चीन के ऊपर नजर रखने के लिए उसकी जरूरत समझते थे इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य सरकार द्वारा अपने ही देश के लोगों के साथ किए जा रहे व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया। आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारतीय सहायता से अपनी मुक्ति वाहिनी का निर्माण किया जिसने पाकिस्तानी सैन्य बलों से प्रतिरोध की शुरुआत की। शरणार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी जारी की जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर आक्रमण शुरू कर दिया जवाब में भारत ने न सिर्फ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का सामना किया बल्कि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में मान्यता देते हुए वहां सैन्य हस्तक्षेप किया और16 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। पाकिस्तान की निर्णायक पराजय के साथ पूर्वी

पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और भारत सरकार की सहायता से उसे वैश्विक मान्यता मिलनी शुरू हो गई। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब बहुसंख्यकों ने अर्थात पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अल्पसंख्यकों अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान से सफलता पूर्वक खुद को अलग कर लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी के दबाव में पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाई हुई जिन्होंने बांग्लादेश में नई सरकार का निर्माण किया। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया और कहा कि वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। भारत ने नव स्वाधीन बांग्लादेश को न सिर्फ कूटनीतिक मान्यता दिलवाई बल्कि उसे तमाम तरह की आर्थिक तकनीकी और सैन्य सहायता भी प्रदान की ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके और एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत का आदर्श पड़ोसी बने और दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हुए विकास कर सकें।

बांग्लादेश की आजादी के कुछ ही वर्ष पश्चात 1975 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की उनके पूरे परिवार के साथ वहां के सैन्य और राजनीतिक षड्यंत्र में हत्या कर दी और आगे चलकर मेजर जनरल जियाउर रहमान ने बांग्लादेश में सैन्य शासन की नींव डाली। आगे चलकरजियाउररहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की, अपने शासन को नागरिक शासन का रूप दिया और धीरे-धीरे बांग्लादेश के इस्लामिक तत्वों के साथ मिलकर बांग्लादेश का इस्लामीकरण शुरू कर दिया। उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की भारत से मित्रता की 'भारत प्रथम नीति' से दूरी बनानी शुरू कर दी तथा पाकिस्तान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व के इस्लामी देशों के साथ संबंधों को जोर-जोर से बढ़ाना शुरू कर दिया। आगे चलकर बांग्लादेशीसेना के कुछ असंतुष्ट तत्वों ने जियाउररहमान की भी हत्या कर दी। एक अन्य सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने बांग्लादेश की कमान संभाली और बांग्लादेश को लगभग इस्लामी राष्ट्र बना दिया गया। इस दौर में शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना वाजेद जो अपने पिता और परिवार की हत्या के समय विदेश में होने के कारण बच गई थी और आगे चलकर भारत की शरण में रह रही थी, बांग्लादेश वापस आई और अवामी लीग का नेतृत्व संभाल लिया। जियाउर रहमान की विधवा बेगम खालिदा जिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व को संभाला। बांग्लादेश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन शुरू हुआ और 1991 में चुनाव पश्चात खालिदा जिया ने जमाते इस्लामी की सहायता से सरकार बनाई। जमाते इस्लामी एक पाकिस्तानपरस्त धार्मिक संगठन था जो बांग्लादेश के निर्माण का विरोधी था और उसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के सैन्य तंत्र की बहुत मदद की थी। बांग्लादेश की स्वाधीनता के पश्चात इसने बांग्लादेश में शरीयत आधारित इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना के लिए काम करना शुरू कर दिया था। खालिदा जिया के शासनकाल के दौरान वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अत्याचार बढ़ गया, उनके धर्मस्थलों को पवित्र किया गया लूटपाट की गई उनको तोड़ फोड़ा गया और कई धर्मस्थलों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई और सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटनाएं आम हो गई जिसके कारण बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग समय-समय पर भारत में शरणार्थी के रूप में आते रहे। हालांकि इसी दौर में भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगाजल बंटवारे का समझौता भी किया और बांग्लादेश को अपनी ओर से व्यापारिक संबंधों में मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी दिया। 1996 के चुनाव में अवामी लीग की जीत हुई और शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश का नेतृत्व संभालते ही अपने पिता के अनुरूप भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। उनके शासन में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं में कमी दर्ज की गई। विभिन्न कारणों से अवामी लीग 2001 के आम चुनाव में पराजित हुई और पुनः खालिदा जिया की सरकार बनी जिसने पुराना दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया। इस काल में भारत के पूर्वी प्रदेशों के उग्रवादियों को हथियार,धन प्रशिक्षण और शरण देने का काम बांग्लादेश ने किया जिसके कारण दोनों देशों के संबंधों में गर्मजोशी का अभाव देखा गया। 2006 में बांग्लादेश के आम चुनाव में आवामी लीग को पुनः जीत हासिल हुई और शेख हसीना एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने भारत प्रथम की नीति को फिर से बांग्लादेश की विदेश नीति का सूत्र बनाया। दूसरी और बांग्लादेश के विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया की भारत की खुफिया संस्था अनुसंधान और विश्लेषण शाखा (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) ने आवामी लीग के समर्थन में बांग्लादेश के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जिसका भारत ने पुरजोर खंडन किया।

2014 के भारतीय आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जीत हासिल हुई और नरेंद्र मोदी को सरकार का नेता चुना गया। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के सभी पड़ोसी देश के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद भी शामिल थी। नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश के संबंधों में प्रगति और बढ़ी। इस काल में भारत ने बांग्लादेश को आधारभूत ढांचे के विकास और औद्योगिक संरचना के निर्माण के लिए खुलकर मदद दी। भारत ने बांग्लादेश

के व्यापारियों, विद्यार्थियों और मरीजों के लिए आसान वीजा नियमों का प्रावधान किया। बांग्लादेश ने भी भारत को अपने क्षेत्र से होकर पारगमन की सुविधा दी जिसके तहत भारत सामान्य शुल्क चुका कर अपने मालवाहक वाहनों द्वारा सड़क मार्ग से अपने पूर्वोत्तर के राज्यों तक विभिन्न प्रकार के सामानों का आसानी से कम समय में परिवहन कर सकता है। बांग्लादेश ने भारत को ब्रह्मण बरिया और चटगांव बंदरगाहों के प्रयोग के लिए भी सहमति दी। इससे भारत पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी से अपने पूर्वी राज्यों तक कम समय, कम खर्चे में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर सकता है जो की सिलीगुड़ी कॉरिडोर् से करने पर अपेक्षाकृत अधिक समयसाध्य और खर्चीली है। बांग्लादेश ने शेख हसीना के शासनकाल में भारत के रणनीतिक हितों का ध्यान रखा और चीन को बांग्लादेश में पूंजी निवेश की अनुमति देते हुए भी ऐसी परियोजनाएं सौंपने से दूरी बनाई जिनका उपयोग वह भारत के विरुद्ध अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए कर सके। शेख हसीना ने पाकिस्तान को बांग्लादेश में पैर जमाने का कोई अवसर नहीं दिया। हालांकि भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता के इस दौर में तीस्ता जल समझौता नहीं हो पाया जिसकी कसक बांग्लादेश को बार-बार उठती रही। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय से ही बांग्लादेश के विपक्षी दल विशेषकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अरे जमात ए इस्लामी भारत पर आरोप लगाते रहे हैं कि वह बांग्लादेश के सभी दलों से संबंध नहीं रखता है, भारत अपना सारा निवेश एक व्यक्ति विशेष में कर रहा है जिनका नाम शेख हसीना है और वह भी भारत के हितों को बांग्लादेश के हितों से अधिक प्रधानता देती हैं। दूसरी और भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और भारत बांग्लादेश के लोगों के चहुमुखी विकास के लिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्पित है और शेख हसीना की सरकार का इसलिए समर्थन करता है क्योंकि बांग्लादेश के लोगों ने उनके नेतृत्व में संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया है।

जनवरी 2024 में शेख हसीना वाजिद के नेतृत्व में अवामी लीग को बांग्लादेश के आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था। बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भारत के दबाव में बांग्लादेश की कुछ विपक्षी पार्टियों ने आम चुनाव में भागीदारी की ताकि बांग्लादेश के चुनाव को लोकतांत्रिक और संवैधानिक करार दिया जा सके। जून2024 में बांग्लादेश के असंतुष्ट छात्रों ने वहां की आरक्षण नीति के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी। बांग्लादेश में 1971 के मुक्तिसंग्राम के योद्धाओं और उनके परिजनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाता था जिसे लेकर यह छात्र संतुष्ट नहीं थे। हालांकि शेख हसीना की सरकार ने पहले इस आरक्षण का दायरा सीमित कर दिया और फिर समाप्त भी कर दिया लेकिन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर इसे बहाल कर दिया था। बांग्लादेशी असंतुष्ट छात्रों ने आरोप लगाया की शेख हसीना की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चोर दरवाजे से अपने समर्थकों को सरकारी सेवाओं में घुसने का रास्ता फिर से खोल दिया है। इस आंदोलन के दौरान शेख हसीना ने पहले तो छात्रों को समझने का प्रयास किया, कुछ कठोर टिप्पणियां भी की और फिर प्रशासन को आंदोलन को कुचलना का आदेश दिया। अगस्त की शुरुआत में आंदोलन अत्यंत हिंसक हो गया। सेना तथा प्रशासन के लोगों ने शेख हसीना के सामने स्पष्ट कर दिया कि वह आन्दोलनकारिओं पर पर बल प्रयोग नहीं करेंगे जिसके कारण शेख हसीना लाचार हो गई। असंतुष्ट छात्रों की भीड़ अवामी लीग के नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला करने लगी उनकी संपत्ति में आग लगाने लगी और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की परिवार के साथ बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब हिंसक भीड़ शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास 'बंगभवन' की ओर बढ़ने लगी और सेना ने उनके साथ छोड़ दिया तो शेख हसीना को मजबूर होकर भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना ने भारत आने के पश्चात खुलासा किया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वह नहीं चाहती थी की बांग्लादेश की सेना छात्रों पर गोली चलाए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि अगर वह बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटे से टापू 'सेंट मार्टिन' को सैन्य अड्डा बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप देती तो उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं रहता। शेख हसीना का यह रहस्योद्घाटन इस बात को स्पष्ट करता है की संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र के हिमायती होने का ढोंग करता है और वहां का डीप स्टेट अपने हितों की पूर्ति के लिए कहीं भी अलगाववाद, हिंसा, सैन्य नेतृत्व और यहां तक की आतंकवादियों को भी समर्थन देने से नहीं चूकता है।

शेख हसीना की असमय विदाई के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थक बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता 86 वर्षीय मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेशी छात्रों ने एक तथाकथित सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया। छात्र नेताओं ने कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों और आंदोलनकारी छात्र नेताओं को सरकार के विभिन्न विभागों का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। इस दौरान न सिर्फ अवामी लीग से जुड़े लोगों की हत्या की गई, उनकी संपत्ति बर्बाद की गई बल्कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक

हिंदुओं को विशेष रूप से निशाने पर लिया गया। उनके मूर्तियां और मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया, जलाया गया। हिंदूमहिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। हिंदू व्यवसाईयों को अपने होटल में गौमांस पकाने और ऐसा नहीं करने पर अपना होटल बंद करने को मजबूर किया जा रहा है। सरकारी सेवा में कार्यरत हिंदुओं को नौकरी से इस्तीफा देने को मजबूर किया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्व चाहते हैं की बांग्लादेश के हिंदू या तो इस्लाम स्वीकार कर लें या भारत चले जाएं। हमेशा लोकतंत्र और मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी और इटली जैसे देश हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखकर भी मौन है। बांग्लादेश के अवैध सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस,उनके सलाहकार तथा पूर्व सैन्य अधिकारी लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, भारत को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और कई जिम्मेदार लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी बांग्लादेश का हिस्सा है। भारत बांग्लादेश के साथ सहज संबंध चाहता है और भारत की प्रतिक्रिया उम्मीद से ज्यादा संयम से भरी हुई है।

भारत ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को पटरी पर रखने के उद्देश्य से अपने विदेश सचिव विक्रम मिश्री को बांग्लादेश भेजा लेकिन उनकी यात्रा की समाप्ति पर बांग्लादेश द्वारा दिया गया वक्तव्य दर्शाता है कि बांग्लादेश अब अपनी इस्लामी पहचान को ज्यादा प्रमुखता देता है। बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े हुए स्मारकों को नष्ट कर दिया गया है, पाठ्य पुस्तकों में उनके बारे में पाठ हटाया जा रहा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान 'अमार सोनार बांग्ला' जोकि भारत के कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है को बदलने की बात हो रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज और संविधान को बदलने की भी बात हो रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध भी स्थापित कर लिया है और मोहम्मद यूनुस तथा उनके सलाहकारों की मंडली का कहना है कि 2025 के अंत या 2026 में किसी समय बांग्लादेश में चुनाव होगा लेकिन उसके पहले ऐसे तमाम प्रबंध किए जाएंगे जिससे शेख हसीना की तरह के लोग सत्ता में वापस नहीं आ सके। वहां की सरकार से जुड़े लोग बार-बार कह रहे हैं कि भारत के साथ आर्थिक संबंधों में बांग्लादेश को नुकसान है क्योंकि भारत 12 अरब डॉलर का निर्यात करता है और बांग्लादेश से 2 अरब डॉलर से भी कम का आयात करता है। अभी बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख और तख्तापलट के मुख्य किरदारों में से एक सेनाध्यक्ष जनरल वकार उज जमा ने बांग्लादेश के समाचार पोर्टल बांग्लादेश आलो को दिए साक्षात्कार में कहा की भारत और बांग्लादेश के संबंध लेनदेन पर आधारित हैं जबकि चीन बांग्लादेश के विकास में एक साझेदार है। स्पष्ट है कि बांग्लादेश अब बंगाली संस्कृति को नहीं, बंगाली राष्ट्रवाद को नहीं, बल्कि अपनी इस्लामी पहचान को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। अपने हजारों सैनिकों की प्राणों की आहुति देकर और अपने गरीबों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके जिस भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया उसे अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता दी आज वह भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा शत्रु है। बांग्लादेश भूल गया है कि अपनी 94% सीमा भारत के साथ साझा करता है अर्थात एक तरह से भारत से घिरा हुआ देश है। भारत ही उसे बिजली, पानी, पेट्रोलियम पदार्थ, मशीनरी, मुख्य भोजन सामग्री, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसायन और उर्वरक इत्यादि बहुत आसान तरीके से और बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराता है। बांग्लादेश अपने वस्त्र उद्योग के कारण आज अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार पाया है उसमें मुख्य भूमिका भारत के पूंजीनिवेश और भारत द्वारा सप्लाई किए जाने वाले उपकरणों की है। बांग्लादेश के लोगों की जटिल बीमारियों का इलाज बहुत आसानी से और कम कीमत पर भारत के अस्पतालों में हो जाता है। आज भी 3.5करोड़ से अधिक बांग्लादेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह और रोजी-रोटी प्राप्त कर रहे हैं। सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में भारत ही उसके काम आता है। भारत की सामर्थ्य उससे बहुत बड़ी है। भारत अगर बांग्लादेश बना सकता है तो भारत बांग्लादेश के अस्तित्व को मिटा भी सकता है। आज बांग्लादेश के रवैया के कारण भारतीय जनता के बीच आक्रोश बढ़ रहा है और इससे पहले की यह आक्रोश भारतीय शासन व्यवस्था को मजबूर करे, बांग्लादेश को संभल जाना चाहिए अन्यथा सांप्रदायिक सोच से भरी हुई उसकी नई व्यवस्था उसे एक असफल पाकिस्तान बना देगी।

सन्दर्भ :

1. The Partition of Bengal, 1905: South -sia's first Look East Policy?. The Daily Star. 16 October 2017
2. India and Pakistan: Over the Edge. Time. 13 December 1971.
3. Huque, -hmed Shafiqul; -khter, Muhammad Yeahia (1987). The Ubiquity of Islam: Religion and Society in Bangladesh. Pacific -ffairs. 60 (2): 200-225. doi:10.2307/2758132. ISSN 0030-851X. JSTOR 2758132.
4. Cabinet approves use of Bangladesh ports for Indian shipments to North-East. The Financial Express. 17 September 2018.
5. Bangladesh, India satisfied as 14 Lines of Credit projects completed. The Business Standard. 28 October 2021.
6. - New Bangladesh Is Emerging But It Needs India Too. thediplomat.com. 3 January 2025.
7. Jaiswal, -rushi; News, India TV (9 December 2024). Foreign Secretary Vikram Misri meets Bangladesh's Muhammad Yunus amid strained ties. www.indiatvnews.com.
8. Ejaz, Matiur Rahman,Raheed (1 January 2025). We are amid a new dream, a new time of transition. Prothomalo.